

प्रेषक :-

डा० उमाकान्त पवार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,

उत्तराखण्ड जल-विद्युत निगम लि०,

देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक,

पिटकुल,

देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि०,

देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक, ०७ जून, 2011

विषय :- छठें वेतन आयोग के लागू होने फलस्वरूप मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०-494/XXVII(7)म०कि०/2010 दि० 18-06-2010 द्वारा हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एवं एपेक्स वेतनमान के नियत वेतन के पद के मकान किराया भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण किया गया है। शासनादेश सं०-11/I/2010/05-90/2008 दि० 05-01-2010 द्वारा ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक का वेतनमान रू० 69,010.00-79,000.00 निर्धारित किया गया है, का अधिकतम एच०ए०जी० वेतनमान के बराबर है। अतः वित्त विभाग के शासनादेश सं०-494/XXVII(7)/म०कि०/2010 दि०-18-06-2010 के अनुसार ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक को निगमों द्वारा मकान उपलब्ध न कराये जाने पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार वेतनमान/नियत वेतन के पूर्णकालिक पदों के मकान किराये भत्ते की प्रभावी तिथि तथा अन्य शर्तें उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही यथावत रहेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र सं०-190/XXVII(7)/2010 दि० 01-06-2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक :- यथोक्त।

(डा० उमाकान्त पवार)
सचिव